

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 9 सितम्बर, 2016

विषय: "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत नगर निकायों में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1568/IV(2)-श0वि0-45(सा0)-2015, दिनांक 09.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत 'व्यक्तिगत घरेलू पारिवारिक शौचालय निर्माण' एवं 'सामुदायिक शौचालय निर्माण' हेतु कुल ₹277.00 लाख (केन्द्रांश) की धनराशि अमयुक्त की गयी है। तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: 1/18/2015-SBM, दिनांक 01.07.2016 द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" के उपघटक हेतु अवमुक्त धनराशि कुल ₹277.00 लाख के सापेक्ष देय राज्यांश कुल ₹303.00 लाख (रुपये तीन करोड़ तीन लाख मात्र) की धनराशि की निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

SBM के अन्तर्गत मद	स्वीकृत शौचालयों की संख्या	शासनादेश दिनांक 09.09.2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि (केन्द्रांश)	देय/स्वीकृत राज्यांश
Construction of Individual household latrines (IHHL)	6250	125.00 (द्वितीय किस्त)	125.00
	5000	100.00 (प्रथम किस्त)	100.00
Community Toilet	200	52.00 (40%)	78.00 (60%)
Total-		277.00	303.00

2- उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

- उक्त स्वीकृत राज्यांश की धनराशि कुल ₹303.00 लाख (रुपये तीन करोड़ तीन लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत चयनित नगर निकायों को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर दिया जाय कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।
- "स्वच्छ भारत मिशन" हेतु भारत सरकार द्वारा जारी Guideline एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- पूर्व निर्गत शासनादेशों क्रमशः दिनांक 11.08.2015, 18.12.2015 एवं 09.09.2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूपों पर शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-10-स्वच्छ भारत मिशन-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग शासनादेश संख्या: 965/XXVII(1)/2016, दिनांक 19.08.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

संलग्न-एलॉटमेंट आई०डी० S/1609/2016-65

भवदीय,

(नितिन सिंह मदीरिया)
अपर सचिव।

संख्या- 165- (1)/IV(2)-श०वि०-2016, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
उप सचिव।